



असामान्य

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1981/माघ 27, 1902

No. 56]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1981/MAGHA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, फरवरी 16, 1981

सा० का० नि० 66 (अ).—लुगवी, कागज, गत्ता और अख्तवारी कागज
निर्माण उपकरण नियम, 1980 का प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1)
द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 609 (अ०) तारीख 27 अक्टूबर,
1980 के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड
(i) तारीख 27 अक्टूबर, 1980 में प्रकाशित किया गया था,
जिसमें उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाला राजपत्र जनता को
उपलब्ध करा दिया गया था, साठ दिन के भीतर उन सभी व्यक्तियों से
आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना
थी ;

और उक्त राजपत्र 13 नवम्बर, 1980 की जनता को उपलब्ध करा
दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों
और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कागज और गत्ता
उपकरण नियम, 1981 है ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित
न हो—

(क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है ;

(ख) “उपकरण” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के
अधीन उद्घृहीत और संगृहीत उपकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “कलक्टर” से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और
इसके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपर कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
उप-कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद-
शुल्क अधीक्षक भी हैं ।

(घ) “विकास परिषद्” से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित
कागज, लुगवी और सहबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) “कागज और गत्ता” से सभी प्रकार का कागज और गत्ता
(जिसमें अख्तवारी कागज, पेस्टबोर्ड, मिलबोर्ड, स्ट्राबोर्ड, कार्ड बोर्ड और
नालीदार गत्ता भी सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है ;

(क) "अनुसूचित उद्योग" में अधिनियम की पहली अनुसूची में, 24 क गज और आठों, जिनके अन्तर्गत कागज उत्पादकों] हैं जो वे, के अधीन आने वाला अनुसूचित उद्योग अभिनेत है ;

(ख) अगस्तों और पर्वों के, जो हममें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम या उन नियमों में हैं ।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू होना :- इन नियमों में अन्यथा उपरिष्ठित के सिवाय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्क के प्रतिपादय से सम्बंधित उपबंध भी हैं, आदित्य, उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कागज और गत्ते पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बंध में लागू होते हैं ।

4. निर्यात के मद्दे उपकर का कोई प्रतिपादय नहीं :- भारत में निर्यात किए गए कागज और गत्तों पर उपकर का कोई प्रतिपादय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

5. विवरणियाँ प्रस्तुत करना :-

- (1) प्रत्येक विनिर्माता प्रत्येक मास की 10 तारीख को या उसके पूर्व इन नियमों के उपबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने कारखाने में विनिर्मित और वहां से हटाए गए कागज और गत्ते को मरों के मारे स्ट्राक से सम्बंधित विवरणों कलक्टर को या विकास परिषद् को प्रस्तुत करेगा ।
- (2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में कलक्टर या विकास परिषद् के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह गलत या झुटिपूर्ण है तो कलक्टर या विकास परिषद् विनिर्माता पर सूचना की तामील कर सकेगी जिसमें उससे उसके द्वारा उत्पादित कागज और गत्ता से सम्बंधित अपने सभी खातों या किसी खाते को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ।

6. उपकर के आगम :- उपकर के आगम सर्वप्रथम भारत की समेकित विधि में "038--संघ उत्पाद-शुल्क--वस्तुओं पर उपकर--कागज" शीर्ष के अधीन जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्पत्क समायोजन के पश्चात् विकास परिषद् को ऐसी राशियाँ दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

7. खाता खोलना :- नियम 6 के अधीन विकास परिषद् को प्राप्त रकम भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोल कर जमा की जाएगी ।

8. विकास परिषद् के लेखे :-

- (1) विकास परिषद् नियम 6 के अधीन उसे प्राप्त रकम के सम्बंध में उचित लेखा रखेगी ।
- (2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

9. विकास परिषद् के बजट प्राककलन :-

- (1) विकास परिषद् प्रति वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और उससे ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो केन्द्रीय सरकार नियत करे, मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
- (2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट की मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक कोई खर्च नहीं किया जाएगा ।

(3) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जिन्हें केन्द्रीय सरकार समर्थ-समय पर जारी करे तैयार किया जाएगा ।

10. प्रयोजन जिनके लिए उपकर-आगमों का उपयोग किया जाएगा : अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त उक्त धारा के अधीन संग्रहीत उपकर के आगमों का, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा ; अर्थात् :-

- (1) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान का निर्माण और विकास करने के लिए ;
- (2) कागज, गत्ता और प्रसबारी कागज उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए ;
- (3) अन्य अभिकरणों जैसे वन अनुसंधान संस्थान में बहु विधा विषयक समन्वित अनुसंधान परिशोधनों को प्रोत्साहित देने के लिए विशेष प्रवाजनों वाले अनुसंधान प्रयोगशालाओं में सम्बद्ध अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए ;
- (4) उत्पादन के लिए लक्ष्यों की मिकागिण करने, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करने और समय-समय पर उनकी प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए ;
- (5) अपचय दूर करने, अधिकतम उत्पादन अभिप्राप्ति करने, क्वालिटी सुधारने और लागत कम करने की दृष्टि से दक्षता के आदर्शों का सुझाव देने के लिए ;
- (6) स्थापित श्रमता के पूर्णतः उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए और अनुसूचित उद्योग, विशेष रूप से कम दक्ष एककों, के कार्यकरण का सुधार करने के लिए उपायों की मिकागिण करना ;
- (7) बहुरत विपणन के लिए इंतजामों का संप्रवर्तन करना और अनुसूचित उद्योग के उत्पाद के वितरण और विक्रय की पद्धति के उपाय खोजने में ऐसी सहायता करना, जो उपभोक्ता के लिए समाधान प्रद हो ।
- (8) उत्पादों के मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;
- (9) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता करना और अनुसूचित उद्योग के लिए सामग्री अभिप्राप्ति करने के लिए इंतजामों का संप्रवर्तन करना ;
- (10) सामग्रियों और उपस्कर के बारे में तथा उत्पादन की पद्धति, प्रबंध और श्रम उपयोग के बारे में, जिसके अन्तर्गत नई सामग्री, उपस्कर और पद्धतियों की खोज तथा विकास और पहले से ही उपयोग में आने वालीयों में सुधार भी है, उनमें विभिन्न विकल्पों के फायदों के निर्धारण और प्रायोगिक स्थापनों और वाणिज्यिक पैमानों पर परीक्षण का संचालन करने के बारे में जांच संप्रवर्तित करना या कराना ;
- (11) अनुसूचित उद्योग में लगे हुए या लगाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उससे सम्बंधित तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना ;
- (12) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर अनुसंधान और अनुसूचित उद्योग द्वारा प्रयुक्त माल और सेवाओं के उत्पादन और उपयोग या उपयोग से सम्बंधित विषयों पर अनुसंधान का संप्रवर्तन करना या कराना ;
- (13) लेखांकन और लागत निकालने की पद्धति और व्योहार में सुधार और मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;
- (14) आकड़ों के संग्रह और सूत्रीकरण का संप्रवर्तन करना या कराना ;

- (15) श्रम उत्पादकता में अभिवृद्धि करने के लिए उपाय अपनाने की, जिनके अंतर्गत सुरक्षित और बहुर कार्यकारी दशाएं सुनिश्चित करने के लिए उपाय और कर्मचारों के लिए सुख सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों की व्यवस्था और उनमें सुधार भी है, संप्रवर्तित करना;
- (16) अनुसूचित उद्योग संबंधी उन विषयों पर (जो पारिश्रमिक और नियोजन की शक्तों से भिन्न हैं) जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् से सलाह देने का अनुरोध कर सकती है,

- सलाह देना और ऐसी सलाह देने के लिए विकास परिषद् को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ जांच करवाना ;
- (17) अनुसूचित उद्योग को प्राप्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और ऐसे विषयों पर सलाह देने के लिए जिनसे विकास परिषद् अपने किसी कृत्य का पालन करने में संबद्ध है, हमजाम करवाना;
- (18) ऐसे न्यूनतम प्रशासनिक व्यय पूरे करना जो उसके कृत्यों के निर्वहन में होने हैं। इसके अंतर्गत विकास परिषद् के सदस्यों का यात्रा भत्ता भी है।

उपाबन्ध

(नियम 5 देखिए)

कागज और गत्ता उपकर नियम, 1981 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्ररूप

.....को समाप्त होने वाला मास						रैंज.....			
कारखाने का नाम.....						प्रभाग.....			
पता.....						कलकटरी.....			
क्र० सं०	साल का वर्णन	आदि अतिशेष विनिर्मित		हटाया गया मास		हटाई गई मात्रा पर उद्ग्रहणीय उपकर की रकम	हटाई गई मात्रा पर संदेस्त उपकर की रकम	अन्य अतिशेष	टिप्पणियां
		मात्रा	मात्रा	मूल्य	मात्रा			मात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पण :—मास की प्रत्येक किस्म की बाबत प्रविष्टि अलग-अलग दी जानी चाहिए।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दर्शित विशिष्टियों का अपने कारखाने के अभिलेखां और बहियों से मिलान कर लिया है और वे जहाँ तक मैं/हम सुनिश्चित कर सकता हूँ/सकते हैं, सही और पूर्ण हैं।

विनिर्मिता के हस्ताक्षर

[का० सं० 3(89)/80-कागज]

बी० आर० आर० भयगढ़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1981

G.S.R. 66(E).—Whereas the draft of the Pulp, Paper, Paper Board, and Newsprint Manufactures Cess Rules, 1980, was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3—Sub-section (i), dated the 27th October 1980, with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. G.S.R. 609(E), dated the 27th October, 1980, as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within sixty days from the date on which the Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 13th November, 1980;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Paper and Paper Board Cess Rules, 1981.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (b) "Cess" means the cess levied and collected under sub-section (1) of section 9 of the Act;
- (c) "Collector" means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;

(d) "Development Council" means the Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries, established under section 6 of the Act;

(e) "Paper and paper board" means paper and paper board, all sorts (including newsprint, pasteboard, mill board, strawboard, cardboard and corrugated board);

(f) "scheduled industry" means the scheduled industry falling under the heading '24. Paper and Pulp including Paper Products' in the First Schedule to the Act;

(g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, have the meanings respectively assigned to them in that Act or those rules.

3. Application of Central Excises and Salt Act and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty, shall, so far as may be, apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on paper and paper board under that Act and the rules made thereunder.

4. No Refund of Cess on account of Exports.—No refund of cess shall be allowed on the paper and paper board exported from India.

5. Submission of returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a return in the Form specified in the Annexure to these rules relating to all stocks of items of paper and paper board manufactured in, and removed from, his factory during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the said return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective, the Collector or the Development Council may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the paper and paper board produced by him.

6. Proceeds of the Cess.—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head '038-Union Excise Duties—Cess on Commodities—Paper' and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary.

7. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under rule 6 shall be kept in an account with the State Bank of India.

8. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

9. Budget estimates of the Development Council.—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

10. Purposes for which the Proceeds of the Cess shall be utilized.—In addition to the purposes specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (4) of section 9 of the Act, the proceeds of the cess collected under the said section may, with the approval of Central Government, also be utilised for the following purposes, namely :—

- (i) to build up and develop the Central Pulp and Paper Research Institute;
- (ii) to undertake research in the field of the paper, paper board and newsprint industry;
- (iii) to assist related research and development activities in other agencies such as Forest Research Institute, research laboratories with specific purpose of promoting multi-disciplinary coordinated research projects;
- (iv) recommending targets for production, coordinating production programmes and reviewing progress from time to time;
- (v) suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste, obtaining maximum production, improving quality and reducing costs;
- (vi) recommending measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the working of the scheduled industry, particularly of the less efficient units;
- (vii) promoting arrangements for better marketing and helping in the devising of a system of distribution and sale of the produce of the scheduled industry which would be satisfactory to the consumer;
- (viii) promoting standardisation of products;
- (ix) assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrangements for obtaining materials for the scheduled industry;
- (x) promoting or undertaking inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilisation, including the discovery and development of new materials, equipment and methods and of improvement in those already in use, the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commercial scale;
- (xi) promoting the training of persons engaged or proposing engagement in the scheduled industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto;
- (xii) promoting or undertaking scientific and industrial research, research into matters affecting industrial psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use of goods and services supplied by the scheduled industry;
- (xiii) promoting improvements and standardisation on accounting and costing methods and practice;
- (xiv) promoting or undertaking the collection and formulation of statistics;
- (xv) promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers;
- (xvi) advising on any matters relating to the scheduled industry (other than remuneration and conditions of employment) as to which the Central Govern-

ment may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise;

(xvii) undertaking arrangements for making available to the scheduled industry information obtained and for advising on matters with which the Develop-

ment Council is concerned in the exercise of any of its functions;

(xviii) defraying such minimum administrative expenses as may be involved in the discharge of its functions including travelling allowance for the Members of Development Council.

ANNEXURE

(See rule 5)

Form of Monthly Return to be submitted under the Paper and Paper-board Cess Rules, 1981

Month ending_____

Range_____

Name of Factory_____

Division_____

Address_____

Collectorate_____

Serial No.	Description of the goods	Opening Balance Quantity	Manufactured Quantity	Goods removed Value Quantity		Amount of cess leviable on the quantity removed	Amount of cess paid on the quantity removed	Closing Balance Quantity	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Note:—Separate entry should be made in respect of each variety of the goods.

I/We declare that I/we have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory and that they are, in so far as I/we can ascertain, accurate and complete.

Date.....

Signature of Manufacturer

[F.No.3(89)/80-Paper]

B.R.R. IYENGAR, Jt. Secy.

